भूमिका

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते है। किसी भी राष्ट्र या समाज का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक की विकास प्रक्रिया में सभी का सक्रिय योगदान सुनिश्चित न हो। वर्तमान में भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इस बढ़ती आर्थिक निर्भरता में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाय तो देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का है जो उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था की सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए निरंतर कार्यरत हैं।आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में महिलाओं की अहं भूमिका रही है। हालांकि महिलाओं को हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है भले ही उनका स्वरूप कुछ अलग हो। परिवार के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में भी महिलाओं की अहम भूमिका रही है।

19वीं सदी के शुरुआत से ही समाज सुधार आंदोलनों के जरिये महिलाओं की स्थिति में सुधारात्मक परिवर्तन लाने के बहुत सारे प्रयास हुए। इस दौरान बहुत सारी महिलाएं भी आगे आयीं। 20वीं सदी के शुरुआती दौर तक आते-आते महिलाओं के अधिकारों को लेकर सक्रियता बढ़ने लगी,अनेक महिला संगठनों एवं मजदूर संगठनों के प्रयासों से कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन भी आये है। महिलाएं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग होने लगी। कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के लिए अनेक महिला संगठनों एवं मजदूर संगठनों ने प्रयास किये और कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन भी आये। कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के साथ स्वयं को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने एवं अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में प्रयासरत हुई।

महिलाओं को हर क्षेत्र में पूर्ण एवं समान भागीदारी सुनिश्चित करने एवं उसमें आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु वैश्विक स्तर पर भी सशक्त प्रयास किए जाते रहे हैं [1]। आठ मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समस्त विश्व की महिलाओं की एकता,अस्मिता और स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक है। दुनिया के कोने –कोने में महिलाओं ने अपने मानवीय हक हासिल करने हेतु एकजुट लड़ाई की शुरुआत इसी दिन से की थी। 8 मार्च 1857 के दिन अमेरिका के सूती कपड़ा उधोग में काम के घंटे 16 से 10 करने के लिए सर्वप्रथम मताधिकार आन्दोलन की शुरुआत की।

[1] कुमार राधा,स्त्री संघर्ष का इतिहास,वाणी प्रकाशन

आठ मार्च 1883 में महिलाओं को अपने लम्बे और जुझारू आन्दोलन के फलस्वरूप सर्वप्रथम मताधिकार हासिल हुए और 1910 में समाजवादी औरतों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नारी मुक्ति आन्दोलन की महान नेत्री (क्लारा जेटकिन) के प्रस्ताव पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ऐसे तो इसके पहले भी कई देशों में पुरूषों के समान अधिकार हासिल करने के छिटपुट प्रयास का इतिहास में जिक्र है,लेकिन 19 वी शताब्दी के उतरार्ध से लेकर वर्तमान दोर में महिला आंदोलन दुनिया के हर देश में अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने में सफल रहा,जिसका श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है । 8 मार्च 1915 में ओस्लो में महिलाओं ने एकजुट होकर विश्वयुद्ध का विरोध किया । 8 मार्च 1917 को रूस में रोटी और शांति के नारे के साथ महिलाओं ने अक्टूबर क्रांति की आगुवाई की । 8 मार्च 1937 में स्पेन की महिलाओं ने फ्रेको की तानाशाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया ।8 मार्च 1943 में इटालियन महिलाओं द्वारा मुसोलनी की तानाशाही का विरोध किया गया । 8 मार्च 1974 में वियतनामी महिलाओं ने अमरीकी सामार्राज्यवाद के खिलाफ आवाज उठाई। 8 मार्च 1975 से 8 मार्च 1985 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित कर पुरे विश्व के साथ भारतवर्ष में महिला आन्दोलन की दिशा निर्धारित की गई ।[2]

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष तथा 1975-1985 को महिला दशक घोषित किया गया । इस घोषणा से यह महसूस किया गया कि महिलाओं की दशा सुधारने से समूचे समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा । इस आशय से वर्ष 1985 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वर्ष 2000 तक महिलाओं के सम्पूर्ण एवं समान भागीदारी में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सभी सरकारों को उचित एवं युक्तिसंगत नीतियाँ बनानी चाहिए । यह भी स्पष्ट किया गया कि आर्थिक स्वतंत्रता आत्म-निर्भरता की एक जरूरी शर्त है ।

भारतीय संदर्भ में देखें तो 90 के दशक से ही देश की आर्थिक नीति वैश्वीकरण की दिशा में बढ़ चुकी थी । भूमंडलीकरण(वैश्वीकरण) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1950के दशक में फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय संबंध के साहित्य में किया गया। भूमंडलीकरण का प्रचलन हाल ही के वर्षो में उस समय हुआ जब अचानक सूचना एवं प्रोधोगिकी के क्षेत्र में तथा कथित क्रांति हई । भूमंडलीकरण ऐसी बहुमुखी घटना है जिसका प्रभाव मानव के सामाजिक,आर्थिक तथा राजनैतिक सभी क्षेत्रों में पड रहा है ।[3] भूमंडलीकरण का सीधा सम्बंध बाजार से है ।

[2] नारी संवाद विचारशील एवं संघर्ष महिलाओं की पत्रिका(82 वा अंक)

[3] अंतरराष्ट्रीय सम्बंध सिधान्त एवं समस्याएं –इनंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ MPs.002

भूमंडलीकरण की अवधारणा को आर्थिक रूप से इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि यह विभिन्न देशों के बिच निर्बाध आर्थिक सम्बंधो की ऐसी प्रक्रीया है जो एक निश्चित और सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय शर्तो एवं नियमों से निर्देशित होती है । वास्तविकता यह है कि भूमंडलीकरण ने अधिक मुक्त बहुपक्षीय व्यापर–व्यव्स्था को फलीभूत किया। जवाहर लाल कोल अपनी पुस्तक 'हिंदी पत्रकरीता का बाजार भाव ' में भूमंडलीकरण की व्याख्या कुछ इसी प्रकार से करते है – 'ग्लोबलाइजेशन या वेश्वीकरण वैसा ही शब्द बनता जा रहा है । जैसे कभी कम्युनिज्म (साम्यवाद) और कल तक पूंजीवाद थे । एक नारा, एक विचारधारा,एक समरनीति और एक सपना भी, लेकिन यह है क्या, जिसे कुछ लोग 'पापवृति' तो कुछ लोग मानव जाति के सुखद भविष्य का विराट कार्यक्रम मानते है। सामान्यत: भूमंडलीकरण विश्व के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धो,सहयोग और विनिमय को व्यापकता तथा विश्व व्यापार को निर्बाध विस्तार देने की ही प्रक्रिया है । लेकिन कोई भी सरल धारणा व्यवहार में सरल नहीं रहती, दो देशों के आपसी रिश्तों में देशों की प्रभुसत्ता,देशी कानून,परम्परायें , भू –सामाजिक प्राथमिकताये और सांस्कृतिक मानताए अवरोधको से समझोता करना, उन्हें लाघंन या बदलना,किसी-न किसी तरह पार करना आवश्यक है । इसलिए आर्थिक सहयोग और रिश्तों की गहराई तथा व्यापकता के दायरे में कहीं-न कहीं राजनैतिक ,सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी आते है ।[4]

भूमंडलीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें भौतिक, राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इत्यादी चीजों का एक स्थान से दुसरे स्थान पर हस्तांतरित होता है उसे भूमंडलीकरण कहते है भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में एक देश दुसरे देश पर निर्भर हो जाता है और लोगो के बीच की दूरिया घट जाती है । एक देश अपने विकास के लिए दुसरे देश पर निर्भर रहता है । उदाहरण के लिए सूती कपड़े के उधोग में महत्वपूर्ण नामों में से एक जापान ,भारत या अन्य देशों में हुई कपास पर निर्भर करता है। काजू के अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमुख भारत अफ्रीका देशों में पैदा हुए कच्चे काजु पर निर्भर है । हम सब जानते है की अमेरिका का सूचना प्रद्योगिकी उद्योग किस सीमा तक भारत और अन्य विकासशील देशों के इंजीनियरों पर निर्भर करता है । भूमंडलीकरण में केवल वस्तुओं और पूंजी का ही संचलन नहीं बल्कि लोगों का भी संचलन होता है ।[5] भूमंडलीकरण के कारण हम एक दुसरे के नजदीक आ गये है और राजनीति,सामाजिक आर्थिक ,व्यापारिक ,शैक्षिक,सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में हम एक दुसरे से परिचित हुए है । भूमंडलीकरण का भारत पर नकारात्मक प्रभाव कृषि में हम देख रहे है की हमारी उपजाऊ भूमि

[4] भूमंडलीकरण और मिडिया,शर्मा कुमुद,प्रकाशक:ग्रंथ अकादमिक,संस्करण:प्रथम,2003,नई दिल्ली 110002
[5] http://wimi:wordpress.com

उद्योगों के लिए बिक रही है। हमारे किसान भूमिहीन मजदूर में तब्दील होते जा रहे है। कृषि उत्पाद महंगे होते जा रहे है ,दाले महंगी हो रही है। हमे बाहर से इनका आयात करना पड रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं महंगे बीजों व कृषि नियंत्रकों ने हमारी कृषि को घाटे का सौदा बना दिया है, अधिक –से अधिक पैदावार की लालसा ने अधिक कीटनाशक व उर्वरको के प्रयोग से हमारी कृषि भूमि बंजर बनतीजा रही है विश्व व्यापार संघठन के दबाव में हमारी कृषि नीतियों को बदला जा रहा है। सेज (special economic zone) जिसे हम 20वीं सदी के उपनिवेश अथवा 'देशी जमीन पर विदेशी टापू' कह सकते है के नाम पर गाँव के गाँव उजाड़े जा रहे है। विदेशी निवेशकों को किसान जिसमें महिला-पुरुष दोनों शामिल है। उपजाऊ जमीन कोड़ो के भाव दी जा रही है। जिससे किसान बेरोजगार होकर अन्त में आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है। भूमिहीन के लिए खेती आज घाटे का सौदा बन गयी है कर्ज में डूबे किसान आत्महत्या का रास्ता अपना रहे है। 1971की जनगणना के अनुसार 80%स्त्रियाँ कृषि कर्म करती है। यह संख्या ग्रामीण और शहरी कार्य-शक्ति का क्रमशः 87%और 17.5%है।[6]

भूमंडलीकरण एवंस्त्री

भूमंडलीकरण का प्रभाव स्त्रियों व पुरूषों पर अलग्अलग तरह से पड़ता है। एक तरफ तो भूमंडलीकरण से स्त्रियों को काम के लिए क्षेत्र मिला है वह शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनी है उसकी सामाजिक भूमिका में परिवर्तन आया है घर से बाहर जाने का अवसर मिला है। वहीं दूसरी तरफ स्त्रियों पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। भूमंडली व्यवस्था से स्त्री श्रम का शोषण हो रह है। उसे नई जटिलताओं का सामना भी करना पड़ा रहा है। भारत की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का 50%है। कृषि के मुकाबले कारखाने में कामगार औरतों की संख्या कम है। भूमंडलीकरण ने स्त्री के लिए रोजगार के दरवाजे जरुर खोले है। मगर उसके श्रम का शोषण हुआ है। स्त्री को बड़े समूह में फैक्ट्रियाँ रोजगार देती है क्योंकि उनका श्रम सस्ता होता है। महिलाओं के श्रम को देश के आर्थिक विकास में नहीं गिना जाता है। क्योंकि जो काम महिलाएं करती है जैसे घर का खाना बनाना,जुते बनाना,कपड़े धोना, घर की साफ- सफाई,पति के खाना बनाना लोहे के काम इत्यादि। ज्यादातर श्रम के कार्य घरों के अन्दर किये जाते है। भूमंडलीकरण के बाद से घरों में किए जाने वाले कार्य उधोग-धंधे फ़ैक्ट्रीयों के खुलने के करण बन्द हो गये। अब घरों का सारा काम फ़ैक्ट्रीयों में होने लगा जिसके करण महिलायों का श्रम छिन हो गया।

[6] http://www.pravakta.com

फैक्ट्रीयों में ज्यादा संख्या में पुरूषों को ही चुना जाने लगा और महिलाओं की स्थिति इसके करण हिन होती चली गई। महिलाएं ओवर टाइम काम करती है और उनको मातृत्व अवकाश एवं शिशुग्रह की व्यवस्था भी बहुत कम होती है। अत: उनकी अधिक मांग होती है स्त्री के काम के घंटे भी ज्यादा होते है क्योंकि महिलाएं घर जाकर भी काम करती है। उदहारण के लिए मेक्सिको में मकीलाडोरा कारखाने में काम करने वाली औरते। ये ऐसे कारखाने है जहां का वातावरण सुविधाहीन,दम घोटू है। इलेक्ट्रोनिक उद्योग में काम करने वाली स्त्रियों को कैंसर का अंदेशा होता है। भूमंडलीकरण के बाद से व्यक्ति बेटियों के व्यापार में कुछ परिवर्तन हो रहे है। अब उन्हें सीधे नहीं बेचा जाता बल्कि माता-पिता या उसके अभिभावक उसे गिरवी रखकर ऋण लेते है। जिससे की लड़की की भूमिका गोण होती है।

भूमंडलीकरण ने औरतों को अतीत की किसी भी कलावधि के मुकाबले अधिक निर्ममता और सम्पूर्णता से एक बिकाऊ जिंस में बदल दिया है। भूमंडलीकरण के पिछले दस वर्षो में यानि 90 के दशक में दुनिया के पैमाने पर औरतों के निर्यात के जरिये अरबों-खरबों डालर की रकम कमाई गई है। औरतों के निर्यातक देशों के प्रति व्यक्ति आमदनी तकरीबन दुगनी हई है। ये गरीब देश वहीं है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सलाह पर ढ़ाचागत समायोजन कार्यकर्मों को अपनाया था। ये वहीं देश है जिन्होंने विदेशी पूंजी के आने-जाने पर लगी परम्परागत बंदिशो को क्रमशः हटा लिया है। ये भूमंडलीकरण की होड़ में कूदने वाले देश है। लेकिन इससे वे कर्ज के बोझ तले दब गये है। उन्हें कृषि और उधोग के क्षेत्रों से कर्ज उतारने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा नही मिल पा रही है। इसलिए वे औरतों का निर्यात करके डालर और पाउंड हासिल करने में लगे है।" सास्किया का दावा है कि योन व्यापार का यह परिदृश्य सीधे-सीधे भूमंडलीकरण से जुड़ा है ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी वाले इलाकों में योन उधोग सरकारों की मिलीभगत से विकास का जरिया बन गया है। 'सेक्स टूरिज़म' कई एशियाई देशों के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत है। विदेशों मे काम कर रही औरते,चाहे वे योन उधोग मे हो या घरों मे नोकरी करती हो। भूमंडलीकरण के इस युग में सरकारों की विदेशी मुद्रा जरूरते पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाती है। फिलीपींस औरतों के निर्यात के मामले में सबसे आगे है। उसके लिए इससे होने वाली आय विदेशी मुद्रा का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। बांग्लादेशमध्य-पूर्व,जापान और यूरोपीय देशों में अपनी औरतों भेजता है।[7]

[7] भारत का भूमंडलीकरण,सम्पादक :अभय कुमार दुबे

भूमंडलीकरण के दोर में नारी की मुश्किले बढ़ी है बढ़ते हुए मशीनीकरण से नोकरीयों में असुरक्षा ,कम वेतन परम्परागत हुनर की अनदेखी, विदेशी कम्पनियों की मनमानी शर्ते,बड़ते भ्रष्टाचार इन के करण महिलाओं को न्याय दिलाना असमर्थ है । भूमंडलीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाओं के साथ निर्धनता एवं भेदभाव किया ज रहा है । आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के श्रम को सीधा उत्पादन से जोड़ा जाये । 1991 में भारत में जो नई ओधोगिक निति आई इससे निजीकरण,उदाराकिरण व भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है । और भूमंडलीकरण से महिलओं की स्थिति एवं भूमिका दोनों प्रभावित हुई है । भूमंडलीकरण से विकास एवं सुधर की तुलना में महिलाओं का पतन हुआ है ज्यादातर महिलाएं असंगठित संस्थानों में काम करती है । नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती है । संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की स्थिति को बनाने के कई प्रस्ताव दिए है –जैसे:-स्त्री पुरूष के लिए समान कार्य,समान वेतन कानून का प्रावधान इनमें से एक है । उद्योग धंधो में महिला श्रमिकों की मांग,श्रम की कार्य क्षमता से वंचित होना पड़ता है ।[8]

उपर्युक्त संदर्भों के आधार पर एक बात तो कहा जा सकता है कि महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से निर्भर हो रहीं हैं । लेकिन क्या महिलाओं की समस्याएं केवल बाहर जाकर काम करने से दूर हो जाएंगी ? क्या आर्थिक निर्भरता बढ़ने से उनकी परंपरागत भूमिका में कुछ बदलाव आ रहा है ? या दूसरे शब्दों में कहें तो कामकाजी महिलाओं के निजी एवं सार्वजनिक जीवन में क्या कोई सकारात्मक बदलाव आ रहा है ? आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में बेहद महत्त्वपूर्ण और प्रासांगिक हैं । इन संदर्भों को देखते हुये कामगार महिलाओं के निजी एवं सार्वजनिक जीवन में आ रहे बदलावों का अध्ययन करना आवश्यक जान पड़ता है । इन सभी परिदृश्यों को देखते हुए कामगार महिलाओं के निजी एवम सार्वजिनिक जीवन में आ रहे बदलावों का अध्ययन करना आवश्यक जान पड़ता है ।

मैं कुरुक्षेत्र जिले की रहने वाली हूँ । और कृषि परिवार से ही सम्बन्धित हूँ । इसलिए कुरुक्षेत्र जिले में महिलाएं किस प्रकार का काम करती है,कितने घंटे काम करती है,और क्या काम करती है,इसकी मै अवलोकन के माध्यम से जानकारी रखती हूँ । जैसे :-कुरुक्षेत्र में महिलाएं ईट बनाने का काम,दिहाड़ी करना,घर का काम तो करती ही है । साथ ही घर से बाहर दुसरे के मकानों में जाकर साफ़-सफाई,खाना-बनाना,कपड़े धोना,मैड का काम करना,दुसरे के खेतों में जाकर काम करना इत्यादी । यहाँ तक कि जमीन भी महिलायों के नाम पर नहीं है अगर है तो वो

[8] वैश्विकरण के दोर में महिलाऐ,स्वाती शर्मा,संस्करण :07 सितम्बर(2009)

पुरूषों के नाम पर है। जो महिलाएं पढ़ी-लिखी है नोकरी करती है वो नोकरी के साथ-साथ घर का भी काम करती है। इसमें महिलाएं दोहरी भूमिका निभा रही है। इस प्रकार के कामों में ज्यादातर निम्न वर्ग व मध्यम वर्ग की महिलाएं शामिल है। शोधार्थी द्वारा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले जो शोधार्थी का गृह जनपद है। को अध्ययन क्षेत्र के लिए चयनित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर प्रखण्ड के लिए असंगठित क्षेत्र को विशेष रूप से खेतों में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं को शामिल किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए इसे विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया गया है। ताकि इस कार्य को अधिक सुचारू,व्यवस्थित एवं विस्तृत तरीके से किया जा सके व्यवस्थित अध्ययन के लिए प्रस्तावित शोध विषय की रूपरेखा तैयार की गई है।

सैद्धांतिक पृष्टभूमि के अंतर्गत भूमंडलीकरण और उसकी व्यापकता को बताने के साथ ही भारत में भूमंडलीकरण की आरंभिक परिस्थितियों से भी अवगत करने की कोशिश की गई है। श्रमिक महिलाओं पर किस प्रकार भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ाइन विभिन्न मुद्दों पर व्यापक समाज और जानकारी के लिए इस लघु शोध प्रबंध को चार अध्यायों विभाजित किया गया है।

प्रथम अध्याय-'भूमंडलीकरण बदलता आर्थिक सांस्कृतिक भूगोल' है। इस अध्याय में भूमंडलीकरण के संक्षिप्त इतिहास को बताने के साथ ही भूमंडलीकरण ने किस प्रकार कृषि से जुड़ी महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है इसे भी दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण बहसों को भी शामिल किया गया है। जो विशेषकर इन मुद्दों से जुड़े रहे हैं।

दूसरा अध्याय-'कुरुक्षेत्र जिला: शोध का क्षेत्र का इतिहास,महत्व एवं आवश्यकता' है इसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र जिले की ऐतिहासिक भौगोलिक एवं राजनैतिक स्थितियों को बताया गया है। आर्थिक उदारिकरण के पूर्व कुरुक्षेत्र जिले में श्रमिक महिलाओं की क्या स्थिति रही है? इसे भी रेखांकित किया गया है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से श्रमिक स्त्री पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया गया है। साथ ही खेतिहर मजदूर महिलाएं और उनके सामने उभरती चुनौतियां एवं जीवन संघर्ष के बारे में प्रश्नावली के माध्यम जानने की कोशिश की है।

तीसरा अध्याय- 'फैलती दुनिया और सिकुडते हालात:स्त्रियों की नजर से' इसके अंतर्गत मैने 6 महिलाओं का साक्षात्कार लिया है। जिसमें एक महिला का जमीदार से मजदूर बनने, देहरादून से हरियाणा का सफर,असाधारण हिम्मत की मिशाल,संघर्ष का सफर ,एक

महिला के जीवन की आप बीती के बारे में लिखा है। इन सबसे यह जानने की कोशिश की गयी है।

चोथा एवं अंतिम अध्याय में विश्लेषण किया गया है। जो प्रस्तुत शोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भाग में शोध कार्य से प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर कुरुक्षेत्र जिले की श्रमिक महिलाओं की स्थिति का नारीवादी विशलेषण प्रस्तुत किया गया है।

शोध के दौरान प्रयोग में लाई गई समस्त सामग्री (पुस्तके, वेबसाइट, छाया-चित्र, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार-पत्रों की सूची संदर्भ-ग्रंथ के अंतर्गत दी गई है । परीशिष्ट के अंतर्गत क्षेत्र कार्य के दौरान लिए गये छाया चित्र शामिल किए गये है। और अंत में प्रश्ननावली भी शामिल की गई है।

साहित्य का पुनरावलोकन:-

प्रस्तावित शोध शीर्षक के चयन के दौरान शोधार्थी द्वारा शोध से सम्बन्धित साहित्य पुनरावलोकन किया गया है

1. **खेतान, प्रभा. (2007).** ***बाजार के बीच : बाजार के खिलाफ भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न.*****नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.**

यह पुस्तक "प्रभा खेतान'' द्वारा लिखी गई है भूमण्डलीकरण का प्रभाव स्त्री पर भी उतना पड़ा है जितना पुरुषों पर एक तरफ तो भूमण्डलीकरण से स्त्रियों को काम के लिए क्षेत्र मिला है वह शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनी है उसकी सामाजिक भूमिका में परिवर्तन आया है घर से बाहर जाने का अवसर मिला है तो वहीं दूसरी तरफ स्त्री पर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा है भूमंडलीय व्यवस्था ने स्त्री श्रम का शोषण हो रह है उसे नईजटिलताओं का सामना भी करना पड रहा है। भारत की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं की श्रम 50% है कृषि के मुकाबले कारखाने में कामगार औरतो की सख्या कम है भूमण्डलीकरण ने स्त्री के लिए रोजगार के दरवाजें जरुर खोले है मगर उसके श्रम का शोषण हुआ है स्त्री को बड़े समूह में फक्ट्रीयां रोजगार देती है क्योंकि उनका श्रम सस्ता होता है महिलाएं ओवर –टाइम काम करती है और उनको मातृत्व अवकाश एव शिशुगृह की व्यवस्था की जरूरत भी नहीं पड़ती अत: उनकी अधिक मांग होती

है स्त्री के काम के घंटे भी ज्यादा होते है क्योंकि वह घर जाकर भी काम करती है लेकिन उसके काम को काम हि नहीं माना जाता है उदहारण के लिए , मेक्सिको में मकीलाडोरा कारखाने में काम करने वाली औरतें ये एसे कारखाने है जहाँ का वातावरण सुविधाविहिन् ,दमघोटू है इलेक्ट्रोनिक उद्योग में काम करने वाली स्त्रियों को केंसर का अंदेशा होता है भूमण्डलीकरण के बाद से बेटियों के व्यापार में कुछ परिवर्तन हो रहे है अब उन्हें सीधे नहीं बेचा जाता बल्कि माता-पिता या उसके अभिभावक उसे गिरवी रखकर ऋण लेते है जिससे लड़की की भूमिका गोण होती है

2. दुबे, अभय कुमार & यादव, राजेन्द्र & खेतान, प्रभा. (2002). *पितृसता के नए रूप ; स्त्री और भूमंडलीकरण* नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.

इस पुस्तक में "अभयकुमार दुबे'' द्वारा लिखा गया लेख ' पितृसता के नए रूप ' में भूमण्डलीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर लिखा गया है नब्बे का दशक शुरू होने से पहले नारीवादी सिंथिया एनलों ने भूमंडलीकरण के समर्थको से पूछा था की तुम्हारी व्यवस्था में 'औरते कहाँ है ? ' उन्होंने तरह –तरह से खा की औरते राजनीति में है और स्त्री समर्थक राजनेताओं को वोट देने की तैयारी कर रही है इसके अलावा वै निर्यात संवर्धन क्षेत्रों में लगी पड़े पैमाने पर नोकरी कर रही है नई अर्थव्यवस्था ने उन्हें सबसे ज्यादा रोजगार दिया है साथ हि वे फिल्मों में ,मोडलिंग में ,टीवी सीरियलो में ,पॉप संगीत में ,विज्यापनो में और सोंद्रीय प्रतियोगिताओं में छायी हई है वे धीरे-धीरे और बहुराष्ट्रीय निगमों के बिच उनकी प्रबंधन–क्षमता का इस्तेमाल करने की होड़ मची हुई हैं भूमण्डलीकरण से श्रम का स्त्रीकरण हुआ श्रमिको में स्त्रियों की संखया बड़ी ,वैसे हि नर-नारी सम्बन्धो में परिवर्तन आना शुरु हो गया है भूमण्डलीकृत अभियान का एक दूसरा पहेलु भी जो कहीं अधिक सटीक और विश्वसनीय ढंग से साबित करता है की भूमण्डलीकरण ने औरतो को अतीत की किसी कालावधि के मुकाबले अधिक निर्ममता और सम्पूर्णता से एक बिकाऊ जिंस में बदल दिया है सास्किया का दावा है कि योंन व्यापार का यह परिदृश्य सीधे –सीधे भूमंडलीकरण से जुदा है ज्यादा गरीब और बेरोजगारी वाले इलाकों में यौन उधोग सरकारों की मिली भगत से विकास का जरिया बन गया है। 'सेक्स –टूरिज्म' कई एशियाई देशो के लिए आमदनी का प्रमुख स्त्रोत है बांग्लादेश मध्य–पूर्व ,जापान और यूरोपीय देशो में अपनी औरते भजता है बेबेल जैसे समाजवादी विचारको ने घोषणा की थी की मशीनी सभ्यता नारी को आजाद कर देगी मार्क्स की मान्यता थी की एक

श्रमिक के रूप में औरत जैसे ही घर की देहरी से बहार निकल कर पुरुष श्रमिक के बराबर हैसियत प्राप्त करेगी, नर –नारी सम्बन्ध एक नये धरातल पर पहुंचना शुरू हो जाएगे

3. आर्य, साधना& मेनन, निवेदिता& लोकनीता, जिनी. (2001). ***नारीवादी राजनीती संघर्ष एवं मुद्दे*** **नई दिल्ली: हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशायल दिल्ली विश्वविद्यालय.**

यह पुस्तक "नारीवादी राजनीती संघर्ष एंव मुद्दें" साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनिता, द्वारा लिखी गई है इसमें पितृसता को 'सामाजिक सरंचना और क्रियाओं की एक व्यवस्था, के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें पुरुषों का स्त्रियों पर वर्चस्व रहता है,और वे उनका शोषण और उत्पीड़न, करते है इसमें उदारीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, सार्वजनिक निति पर महिलाओं का दृष्टीकोण,राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाएं-भूमिका के सवाल आदि मुख्य बातें लिखी गई है मेरे विषय को लेकर इसमें श्रमिक वर्ग की महिलाओं की बात की गयी है जिसमें 1920 के दशक में श्रमिक वर्ग की महिलाओं में तथा उनके बारे में नई चेतना और चेतनता आई उससे पहले उनके बिच काम के कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गए थे जो किये गये थे वे सुधारवादी थे अभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में निर्धन महिलाओं को जोड़ने के जो प्रयत्न किये गये उसमें उनकी कामकाजी छवि के घरेलू महिला की छवि को ध्यान में रखा गया किसी भी राष्ट्रवादी महिला ने उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संगठित प्रयत्न नहीं किए 1920 के अंत तक कई नामी ट्रेड यूनियनी महिलाए सामने आई वरन श्रमिक महिलाओं ने स्वयं प्रयत्न करके संगठित होना शुरु कर दिया था श्रमिक आंदोलनों में उनकी एक जगह बनी अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी 1930 में हुए अपने ग्वालियर सम्मेलन में श्रमिकों के मुद्दे पर अलग सत्र आयोजित किया मध्यमवर्गीय और निर्धन दोनों ही वर्गो की महिलाओं के लिए उनके मातृत्व-गुणों और भूमिका को ध्यान में रखकर उनके लिए कुछ सिमित कार्यो की ही सोची गई उनकी पाखिरिक पोषण की भूमिका को ध्यान में रखकर उनके लिए पदार्थ व हस्तकला उद्योग आदि काम उपयुक्त सोचे गए जंहा कहीं कुछ अन्य पेंशो में उनके रोजगार के अवसर देखे वंहा भी उनके कामों पर काफी सीमाए निर्धारित की गई इस पुस्तक में 1920 की स्थिति के बारे में बताया गया है लेकिन वर्तमान समय में श्रमिक महिलाओं की किया स्थिति है इसके बारे में नहीं बताया गया है जो मेरे शोध का उदेश्य है

4. कुमार राधा. (2002). *स्त्री संघर्ष का इतिहास.* नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन

यह पुस्तक **'स्त्री संघर्ष का इतिहास' राधा कुमार** द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक में उन्नीसवी सदी से लेकर आज तक भारत में हुए आंदोलनों के संशिप्त व्याखात्म्क इत्हिास की दिशा में एक प्रयास है विशाल देश में दो सो वर्षो की गतिविधियों को इस पुस्तक में वर्णित नहीं किया जा सकता है उन्नीसवी सदी के उतरार्ध की कुछ महिला सुधारको या 20वीं सदी की राष्ट्रवादी महिला नेताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध है इसमें उन्नीसवी सदी, 'राष्ट्र माता' बनती स्त्री, संगठन तथा संघर्ष नारी आन्दोलनकारी छवि का निर्माण, समकालीन नारीवादी आन्दोलन, दहेज-विरोधी आन्दोलन, बलात्कार के विरुद्ध संघर्ष आदि सभी के बारे में बताया गया है 'मानव इतिहास का पहला दुवेत था लैगिक आधार पर श्रम का विभाजन जो स्त्रियों की पुनरुत्पादन योग्यता के कारण उभरा स्त्रियों के जीवन का बड़ा हिस्सा शिशु जन्म,शिशुओं की देखभाल में बिट जाती है जिससे उनकी गतिशीलता कम हो जाती है और वै ग्रहिणी मात्र बनकर रह जाती है जैसे-जैसे समाज पहले कृषि,फिर व्यापार और तत्पश्चात उधोगोन्मुख हुआ, महिलाओं का दायित्व प्रसव,शिशु देखभाल इत्यादी तक सिमित कर दिया गया इस पुस्तक भूमंडलीकरण कोलेकर कोई बात नहीं की गई है .

5. मेहता, जया.; तिवारी,विनीत (अनु.).(2004). *भूमंडलीकरण में महिलाओं का श्रम.* इंदोर (म.प्र.): संदर्भ दस्तावेजिकरण केन्द्र

इसमे बताया गया है की 1970 में भूमंडलीकरण के युग की शुरूआत होती है श्रम मूल्य का स्त्रोत होती है ।और इसका उत्पादन सही अर्थो में पूंजीवादी तरीके से नहीं होता है पूंजीवादी समाज में, श्रम शक्ति भी बाजार में बिकने और खरीदने वाली किसी वस्तु का ही रूप होती है उत्पादन में उपयोग होने वाला कच्चा माल या मशीनरी श्रम के रूप में होता है श्रम को दो हिस्से होते है:एक तो 'सामाजिक हिस्सा' जो बाजार से खरीदी जानेवाली आवश्यकवस्तुओं व् सेवाओं के मूल्य के बराबर होता है दूसरा 'घरेलू हिस्सा' जो परिवार व घर में किया जाने वाला श्रम होता है श्रम के इस घरेलू हिस्से का भार अधिकांशतमहिलाओं पर रहता है, जबकि सामाजिक हिस्से का श्रम अधिंकाशत:पुरुषो की जिम्मेदारी होती घरेलू श्रम का अधिकांश भाग महिलायों द्वारा किया जाता है, अत:महिलाओं के श्रम के एक बड़े भाग का कोई 'आर्थिक मूल्य' नही बनता कृषि क्षेत्र में महिलायों की भूमिका हमेशा से हि रही है पुरुषों व् महिलाओं की गतिविधियों में

आमतोर पर श्रम का स्पष्ट विभाजन रहता है,हलाकि क्षेत्रीय विभिन्नताए भी मोजुद रहती है उदाहरण के लिए बाग्लादेश में धान की खेती के दोरान खेत में की जाने वाली निदाई-गुडाई,खेत जोतना,धान रुपाई,फसल ख़्टाई आदि कार्य पुरुषो की जिम्मेदारी होते है महिलाए बीजों की संभाल,फटकना,उसनना छिलके निकलना आदि घर के नजदीक या घर में रह कर करती है हालांकि धन रोपने का कार्य भारत में महिलाएं करती है, किन्तु ऐसी क्षेत्रीय भिन्नताओं के अतिरिक्त मोटे तोर पर स्त्री-पुरुष का श्रम विभाजन लगभग एक सा ही रहता है भूमंडलीकरण ने इन परिवारों की इस पहले से ही खतरनाक साम्यावस्था को और भी नाजुक,और भी कठिन बना दिया है

6. दुबे,अभय कुमार.(2006). *भारत का भूमंडलीकरण*. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन.

इस पुस्तक में बताया गया है कैसे उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीतियों के कारण राज्य को हानी हो रही है भूमंडलीकरण के विविध दबावों के सामने राज्य और राष्ट्रीय अभिजन कमजोर पड़ते जा रहे है नोकरशाही अब बाहरी एजेंसीयों की तरफ से आने वाले इशारों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखती है और प्रदेश सरकारे विदेशी कार्पोरेशनों तक सीधी पहूँच बनाने की कोशिश में एक-दुसरे से होड़ करती रहती है 'नयी विश्व –व्यवस्था' और उसके तहत हो रहे भूमंडलीकरण का परिणाम राज्य की ताकत के क्षय में निकला है भूमंडलीकरण से राज्य को एक बदलती हुई दुनिया का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण उसके ऊपर तरह-तरह के दबाव पड़ रहे है भूमंडलीकरण से श्रम का स्त्रीकरण हुआ है अर्थात् श्रमिको में स्त्रीयों की संखया बढ़ी ,वैसे हि नर-नारी सम्बंधो में परिवर्तन आना शुरु हो गया भूमंडलीकरण ने औरतों को अतीत की किसी कालावधि के मुकाबले अधिक निर्ममता और संपूर्णता से एक बिकाऊ जिंस में बदल दिया है नब्बे के दशक में दुनिया के पैमाने पर ओंरतो के निर्यात के जरिये अरबों-खरबों डालर की रकम कमायी गयी हैऔरतों के निर्यातक देशों की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले ओंरतो के आयातक देशो में प्रति व्यक्ति आमदनी तकरीबन दुगुनी है योंन व्यापार का परिदृश्य सीधे-सीधे भूमंडलीकरण से जुड़ा हैज्यादा गरीबी और बेरोजगारी वाले इलाकों में योन उधोग सरकारों की मिलीभगत से विकास का जरिया बन गया है पेटमेन का कहना है की किसी जमाने में विदेश जा कर नोकरी करने वाले अधिकांश श्रमिक पुरूष होते थे, लेकिन भूमंडलीकरण के कारण उनमें अब महिलाओं की एक बड़ी सख्या शामिल हो गयी है श्रम-शक्ति के इस स्त्रीकरण से श्रमिकों का उत्पादन में हिस्सा गिर जायेगा दक्षिण कोरिया की भांति भारत में पहले औधोगिक श्रम में

पुरूष उतरे और महिलाओं ने खेतिहर श्रम में उनकी जगह ली भूमंडलीकरण से नस्नारी संबंध या तो बदल गये है या बदलने की दहलीज पर खड़े है यानि जो काम नारीवादी आन्दोलन की पूरी शताब्दी नहीं कर पाई और जो ऐतिहासिक जिम्मेदारी समाजवादी क्रांति के उथल-पुथल भरे दशक पूरी नहीं कर पाये,वह बाजार ने पिछले दस वर्ष में दिखाया है समाज और उसकी विभिन्न संस्थाओं में मोजुद लैगिक अधीनस्थ का लाभ उठा कर भूमंडलीकरण औरतो के श्रम और देह पर निजी नियन्त्रंण को सार्वजिनिक नियन्त्रंण में बदल रहा था पश्चिमी समाजो और पोर्नोग्राफी के संदर्भ में आंद्रिया दुआर्किन द्वारा किए गये विश्लेषण की रोशनी में देखने पर पता चलता था कि बाजार ने किस तरह से औरत को 'प्राइवेट 'से निकाल कर 'पब्लिक ' में लाकर उसका वस्तुकरण करने का अभियान शुरू कर दिया है

7. कारात, बृंदा & उषा, चौहान(अनु.).(2008). *भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति* ग्रन्थ शिल्पी.

इस पुस्तक में अधयाय- 1 में भूमंडलीकरण के खिलाफ सर्भोमिक प्रतिरोध को बताया गया है यह पुस्तक 'भारतीय नारी संघर्ष और मुक्ति' कारात बृंदा' द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक में दशकों से एडवा के सदस्य के रूप में,और 1993 से 2000 तक उसके महासचिव के रूप में,वृंदा कारात संगठन के भीतर और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-जिससे वो जुड़ी थी –के साथ काम करने के अनुभव के जरिए एकत्रित किया है 'इस पुस्तक में 6 अध्याय है महिलाओं की साहयता के लिए एडवा पुरे देश में 50,000 से अधिक मामले देख रहा है ये वै महिलाओं है जो बहुत हि अलग –अलग स्थितियों में कष्ट सह रही है इनमे से अधितकतर ग्रामीण महिलाएं है, कामकाजी महिलाएं है, आजीविका की खोज में छोटी-लंबी दूरियां तय करती महिलाएं है एकल महिलाएं है, बिखरे हुए घरों की निस्सहाय मुखिया महिलाएं है, जातीय,वर्गीय या साम्प्रदायिक हिंसा की शिकार महिलाएं है, इनमें अपने अधिकारों, अस्तित्व और मुक्ति तथा अपने लिए उचित स्थान के लिए हरियाणा से त्रिपुरा तक और केरल से बिहार तक आन्दोलन कर रही महिलाएं शामिल है इस पुस्तक में कुछ चीजें पुरानी है लेकिन अधिकतर 1993-2004 के दशक की है, पुस्तक रोचक 6 खंडो में विभाजित है हर खंड में ऐसे बहुत सारे लेखक है जो व्यापक महत्व के है और विभिन्न विषयों पर है पहले भाग में लंबे निबंध है जो छोटेछोटे अलग-अलग तरह के लेखों से बनाए गये है।'बहुआयामी संघर्षों'वाला पहला खंड 1920 से महिलाओं के आंदोलनों का एक खास इतिहास प्रस्तुत करता है यह वह दुर्लभ पुस्तक है जो

सलीके से लिखी गई है और संतुलित है जो सूचना देती है प्रेरित करती है, लेकिन बिना कुछ भी बोझिल बनाये, हर चीज को हल्के से छुकर यह पुस्तक भारत में महिलाओं के एक बहुत बड़े हिस्से का हर मुश्किल परिस्थितियों के विरुध संघर्ष मात्र अस्तित्व के लिए हाउ;काफी दृष्टि संपन्न है, मुक्ति की लड़ाई के मूल में हमारे देश की ग्रामीण और कामगार वर्ग की महिलाएं है यह पुस्तक कामगार महिलाओं के दृष्टीकोण से लिखी गयी है

8. कृष्णकांत, सुमन.(2001). *इक्कीसवी सदी की ओर*. नयी दिल्ली: राजकमल प्रकाश.

'कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या :आवास' ये लेख प्रवीन कुमार ने लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि जब महिलाये घर से बाहर काम करने आती है उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके बारे में बताया है जिसमे वो एक गुजराती जमुना देवी और शारदा देवी ,बिहार को छोड़ काम की तलाश में दिल्ली आयी है जमुना देवी और शारदा देवी की तरह हजारो महिलाएं महानगरो में किस तरह से अपनी कम आमदनी में,छोटी सी जगह में अस्थायी झुग्गी बनाकर अपनी आवासीय त्रासदी को झेल रही है ,संगठित क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा असंगठित क्षेत्र में खेतो में ,ईनट –भट्ठो पर मज्दुरिनो का काम आदि कार्य कर रही निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं की आवासीय समस्या ज्यादा गम्भीर है करीब- करीब देश के सभी महानगरो में चाहे वह कोलकता हो, चेन्नई हो,मुम्बई हो,या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली,सभी जगह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की आवासीय स्थिति व् समस्या का सवाल एक समान है जहा तक संगठित क्षेत्र में नोकरीपेशा महिलाओं की आवासीय समस्या का सवाल है,तो प्राय: यह देखा गया है कि इसमें भी मध्य आय वर्ग व् निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं की ज्यादा समस्या है राष्ट्रीय श्रम संस्थान की फ़ैलो रीडर डॉ.पूनम चोहान कहती है,असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिला को तो छोड़ ही दे ,संगठित क्षेत्र में तमाम सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को आवासीय स्तर से लेकर कार्यस्थल तक सभी जगह स्त्री होने की पीड़ा को झेलना पडता है यह स्थिति सभी नगर व महानगरो में एक जैसी है महानगरो में कामकाजी महिलाओं की आवासीय समस्या पर,हालांकि अभी तक किसी प्रकार का सर्वक्षण सामने नहीं आया है फिर भी इस क्षेत्र में काम करनेवाले महिला संगठन,समाजशात्रीय विशलेषण के जो अनुभव है, उनके आधार पर यह कहा ज सकता है कि देश के सभी महानगरो में कामकाजी महिलाओं की

आवासीय स्थिति दयनीय है व समस्या गंभीर है खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के आवासीय स्थिति ज्यादा खराब है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का जहां तक सवाल है इसमें सबसे बड़ी मुश्किल यह है की हम उन्हें एक जगह संगठित नहीं कर सकते क्योकि उनका घर और कार्यस्थल दूर-दूर होता है काम करने का समय भी अलग-अलग होता है ये प्राय: अनपढ़ होती है और इनकी आमदनी इतनी अधिक नहीं होती कि वे होस्टल का खर्च दे सके इनके साथ अक्सर परिवार भी होते है इस स्थिति मर उनके लिए सरकार या किसी भी स्वयंसेवी संगठन के लिए आवासीय व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल है अभी तक देश के किसी भी हिस्से में इस में इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया जा सका है

'कृषि क्षेत्र में लगी महिलाओं की समस्याएं' लेख 'मनोज कुमार मिश्र' द्वारा लिखा गया है इसमें इन्होंने लिखा है कि आज के भोतिक युग में हमारे जीवन-मूल्य इस कदर प्रभावित है की कोई भी क्षेत्र इससे अछुता नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा हमारा समाज प्रभावित हुआ है ग्रामीण भारत में सन 1991की जनगणना के अनुसार 27.06 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं है, 48.83 प्रतिशत कृषक मजदूर है इस प्रकार भारत में कृषि क्षेत्र महिलाओं के रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र है और आज की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भारत की प्राय:सभी महिलाओं को किसी- न –किसी रूप में किसान माना जा सकता है ग्रामीण भारत एक ऐसी प्रक्रिया के दोर से गुजर रहा है,जिसे 'कृषि क्षेत्र के महिलाकरण' की संज्ञा दी ज सकती है 1977 और 1991 की अवधि के दोरान पुरुष कृषक मजदूरों की तुलनाओं में महिला कृषक मजदूरों का अनुपात 57 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गय

9. शर्मा, स्वाति. (2009), *वैश्वीकरण के दौर में महिलायें*. संस्करण-07 सितम्बर-

भूमंडलीकरण के दौरमें नारी की मुश्किले बढ़ी है बढ़ते मशीनीकरण से नोकरियों में असुरक्षा,कम वेतन,परम्परागत हुनर की अनदेखी,विदेशी कम्पनियों की मनमानी शर्ते,भड़ते भ्रष्टाचार,इन के कारण औरतो को न्याय दिलाना असमर्थ है भूमंडलीकरण के कारण विकसित देशों में महिलाये निर्धनता एवं भेदभाव किया जा रहा है दोनों के वेतन में भिन्नता है आज जरूरत इस बात की है की महिलाओं के श्रम को सीधा उत्पादन से जोड़ा जाये 1991 में भारत में जो नई औद्योगिक निति आई इससे निजीकरण,उदारीकरण व वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ा है महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण ने विकास एवं

सुधार की तुलना में महिलाओं का पतन हि किया है ज्यादातर महिलाएं असंगठित संस्थाओं में काम करती है नियमहीनता के चलते शोषण का शिकार होती है संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के कई प्रस्ताव दिए है जैसे-स्त्री-पुरुष के लिए सामान कार्य, समान वेतन कानून का प्रावधान इनमें से एक है उद्योग धंधो में महिला श्रमिको की मांग श्रम की कार्य क्षमता वंचित होना पड़ता है ।

10.व्होरा आशारानी.(2005). ***आधुनिक समाज में स्त्री.*****दिल्ली: श्री नटराज प्रकाशन.**

इस पुस्तक में समाज में कामगार महिलाओं की स्थिति क्या है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। जिसमें बताया गया है कि कामकाजी महिलाओं को संगठित क्षेत्र में तो सुविधाएँ मिल जाती है लेकिन असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को बहुत सी सुविधाएँ नहीं मिल पाती है। जैसे:-बच्चों के लिए क्रेच की सुविधाएँ,पानी और खाना इत्यादि । हमारे भारतीय संविधान में जंहा पुरूषों व महिलाओं को सामान काम के लिए 'समान पारिश्रमिक अधिनियम,1976 बनाया गया है । लेकिन समाज में महिलाओं की सच्चाई को देखे तो ये सिर्फ कानूनी कागजों तक सिमित लगता है।

11.भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति,(1974)अलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड 13/14, नई दिल्ली-110001

भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट का सार संक्षेप: (1971-1974) यह रिपोर्ट भारत में महिलाओं की सामाजिक,आर्थिक,शैक्षिक,राजनैतिक स्थितियों की एक विस्तृत रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को संक्षेप में प्रकाशित किया गया।

12.कुमुद,शर्मा,(2003). भूमंडलीकरण और मिडिया,नई दिल्ली.ग्रंथ अकादमी.

इस पुस्तक में भारतीय समाज में भूमंडलीय मिडिया के बुनियादी अन्तर्विरोध क्या हैं? बहुआयामी भूमंडलीकरण के दौर में शक्तिशाली राष्ट्रों में मिडिया-आक्रमण की चुनौती का सामना किस तरह किया जा सकता है? इन्हीं प्रश्नों से जुड़े पहलुओं को टटोलने और खोजने का प्रयास इस पुस्तक मिडिया के परिदृश्य को विश्लेषित करने वाला यह पहला शोध प्रबंध है।

❖ शोध प्रश्न

इस शोध के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख शोधप्रश्न हैं. जो निम्न लिखित हैं:-

- भूमंडलीकरण से पूर्व कुरुक्षेत्र जिले की श्रमिक महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- भूमंडलीकरण के उपरांत कुरुक्षेत्र जिले(हरीयाणा) की श्रमिक महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन हुए ?
- श्रमिक महिलाओं के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां पैदा हुई?

❖ शोध उद्देश्य

- कुरुक्षेत्र जिले में भूमंडलीकरण के प्रभावों का अध्ययन करना।
- भूमंडलीकरण से प्रभावित कुरुक्षेत्र जिले की श्रमिक महिलाओं की समाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- कुरुक्षेत्र जिले में भूमंडलीकरण से श्रमिक महिलाओं के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल करना।

❖ परिकल्पना

शोध प्रश्न और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी कुछ परिकल्पनाएं हैं

- भूमंडलीकरण के दौर मेंकुरुक्षेत्र जिले की श्रमिक महिलाएं दोहरे बोझ का शिकार हो रही हैं।
- कुरुक्षेत्र जिले में श्रमिक महिलाओं के साथ घरेलु हिंसा होती है।
- भूमंडलीकरण के दौर मेंकुरुक्षेत्र जिले की श्रमिक महिलाओं को उनके श्रम के अनुसार पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

❖ शोध का महत्त्व :

किसी भी कार्य का अपना महत्त्व होता है.कुरुक्षेत्र जिले में श्रमिक महिलाओं की क्या स्थिति है शोध से हमे इसकी जानकारी होगी। श्रमिक महिलाएं अपनी मेहनत से दिन में घंटो के

हिसाब से कितनी मजदूरी मिलती है को जाना जा सकता है। श्रमिक महिलाओं को अपने श्रम के दौरान किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है को जाना जा सकता ह। भूमंडलीकरण से महिलाओं को क्या फायदा या नुकसान हो रहा है को जाना जा सकता है।

❖ शोध क्षेत्र का चयन

- इस शोध कार्य के लिए शोधार्थी द्वारा हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले जो शोधार्थी का गृही जनपद है,को अध्ययन क्षेत्र के लिए चयनित किया गया है। इस अध्ययन में कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर प्रखंड के असंगठित क्षेत्र की विशेष रूप से खेतों में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं को शामिल किया गया। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले की कुल संख्या 964,655 है जिसमें 510,976 पुरुष और 453,679 महिलाएं है। कुरुक्षेत्र जिला अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि यह वह क्षेत्र है जंहा महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है। यह हरियाणा के उतर में स्थित है।
- स्थापना :1 नवंबर 1966 को हुई थी।
- कालेज और विश्विद्यालय : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,NIT कुरुक्षेत्र।

❖ शोध प्रविधि

शोध	
गुणात्मक	परिणामात्मक

केस स्टडी			
गैर सहभागी अवलोकन	साक्षात्कार	प्रश्नावली	नमूना सर्वेक्षण

किसी भी शोध कार्य की रुपरेखा को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने हेतु शोध प्रविधि की आवश्यकता होती है। शोध प्रविधि के माध्यम से ही किसी भी शोध कार्य की रूप रेखा निर्धारित की जाती है। शोधार्थी का कार्यक्षेत्र कुरुक्षेत्र जिले की असंगठित क्षेत्र की श्रमिक (खेतिहर

मजदूर) महिलाओं पर केन्द्रित है। शोध के दौरन शोधार्थी द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों का इस्तेमाल कर शोध कार्य को नारीवादी दृष्टिकोण से अंजाम दिया गया है । इसके तहत श्रमिक महिलाओं का व्यक्तिगत अध्ययन (केस स्टडी) साक्षात्कार,प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य संकलन किया गया है । रैंडम सैंपलिग द्वारा अध्ययन हेतु असंगठित क्षेत्र में (खेतिहर मजदूर) महिलाओं का चयन किया गया है । साक्षात्कार के लिए 6 महिलाओं का चयन किया गया है । शोध विषय से सम्बन्धित श्रमिक महिलाओं से प्रशनावली पद्यति का प्रयोग करके खेतों में काम करने वाली महिलाओं से प्रश्नों का उत्तर लिया गया है । शोधार्थी द्वारा अपने शोध विषय से सम्बन्धित अवलोकन पद्यति का प्रयोग किया गया है ।

❖ शोध की प्रवृति

प्रस्तुत शोध की प्रवृति विशलेषणात्मक एवं विवरणात्मक है। जिसके अंतर्गत खेतिहर मजदूर महिलाओं की समस्याओं को जानने और भूमंडलीकरण और आर्थिक नीतियों का श्रमिक महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

❖ शोध की सीमा

शोधार्थी ने अपने शोध विषय के दौरान एक सिमित शोध क्षेत्र का चयन किया। जिसमें की अनुमानित समय में शोध कार्य को पूरा किया। शोधार्थी द्वारा शोध कार्य के लिए श्रमिक महिलाओं की स्थिति को जानने के लिए आकड़े इक्कठे किए गये। इस शोध के अंतर्गत आकड़ो का विश्लेषण गुणात्मक और परिमाणात्मक प्रविधि के तहत किया गया है। मेरा शोध एक साल में पूर्ण हुआ । जिसमे प्रत्येक कार्य यानि सर्वे,साहित्य पुनरवलोकन, प्रश्नावली भरवाने,साक्षात्कार लिया जाना, और थीसिस लिखने इत्यादि के लिए अनुमानित समय का निर्धारण किया । शोधार्थी ने शोध कार्य पूर्ण निष्ठां व ईमानदारी से किया। प्रूफ रीडिंग का भी ध्यान रखा । यही प्रस्तुत शोध की सीमा है।

❖ शोध की नैतिकता

किसी भी शोध कार्य के लिए नैतिकता का होना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत जिन महिलाओं व पुरूषों से प्रश्नावली व साक्षात्कार लिया गया है उनकी गोपनीयता व पहचान को सिमित रखना ही प्रस्तुत शोध की नैतिकता है।

❖ शोध की प्रासंगिकता

प्रस्तुत शोध 'भूमंडलीकरण का श्रमिक महिलाओं पर प्रभाव' (कुरुक्षेत्र जिले के संदर्भ में) हैं। यह शोध नारीवादी दृष्टिकोण से किया जाने वाला शोध है। इसके अंतर्गत भूमंडलीकरण का खेतिहर मजदूर महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को सम्मिलित किया गया है। इन्हीं सब बातों और तथ्यों से इस शोध विषय के चुनाव की प्रासंगिकता सिद्ध होती है।

❖ तथ्य संकलन (प्राथमिक आंकड़ा संग्रह)

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत प्राथमिक आंकड़ा एवं तथ्य संकलन हेतु प्रशनावली के माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की गयी। साथ ही साक्षात्कार,गैर सहभागी अवलोकन,व्यक्तिगत अध्ययन,नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बंध में जानकारी प्राप्त की गयी।

❖ संकलन तथ्य (द्वितीय आंकड़ा संग्रह)

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत द्वितीय आंकड़ा संग्रह एवं तथ्य संकलन हेतु शोध विषय से सम्बन्धित पुस्तकों,पत्र-पत्रिकाओं समाचार-पत्र,छाया चित्रों का प्रयोग भी किया गया है।

❖ तथ्यों/आंकड़ो का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों से प्राप्त तथ्यों व आंकड़ो का विश्लेषण,शोध की विश्लेषणात्मक प्रविधि के अनुसार किया गया है।

भूमंडलीकरण: बदलता आर्थिक-सांस्कृतिक भूगोल

भूमंडलीयअर्थव्यवस्था में आर्थिक रूपसे पुरुष की तुलना में स्त्री को ज्यादा नुकसान हुआ है। स्त्री, दुनिया के कामकाज के कुल घंटों में से दो-तिहाई समय काम करती है लेकिन दुनिया की कुल आय का केवल दसवांहिस्सा ही उसे मिलता है। दुनिया की सारी सम्पत्ति के दसवें भाग की ही वह मालकिन है। 70 के दशक की दुनिया अब बदल चुकी है। चीन,रूस और भारत भूमंडलीकृत बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। इन देशों के पास दुनिया भर के श्रम का आधी हिस्सा है।विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक करोड़ बीस लाख लोगों को नौकरी मिली और तब से यह संख्या बढ़त पर है। इसके चलते श्रम प्रधान उत्पादन विकासशील देशोंतक पहुंचा। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि इन देशों की जनसंख्या का काफी बड़ा हिस्सा गरीबी की सीमा-रेखा से नीचे था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की निवेशीकरण की नीति के कारण इनके जीवन-स्तर में इजाफा हुआ और क्रमशः गरीबी की दर में कमी आई। आज ये देश अपने सस्ते श्रम और उच्च तकनीक से संबंधित उत्पादन क्षमता के कारण विकसित देशों से होड़ करने में समर्थ हैं। श्रम बाजार में स्त्रियों की भागीदारी कोई नयी बात नहीं थी। 19वींसदी के अंत से ही स्त्रियाँ सेवा क्षेत्र, दुकान और ऑफिसों में सक्रिय हो चुकी थीं और जैसे-जैसे जनसंख्या शहरों की ओर अग्रसर होती गई, वैसे-वैसे उद्योगों में स्त्रियों की भागीदारी एवं स्त्रियों के सस्ते श्रम की आवश्यकता भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। साथ ही फोर्डवादी उद्योग व्यवस्था के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में स्त्रियों को समेटना संभव हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा में स्त्रियों की संख्या बढ़ती गई। पश्चिम के श्रम-बाजार में विवाहित स्त्रियों की भागीदारी कम नहीं थी। उन्हें उच्च शिक्षा मिली और इसी कारण 60 के दशक में नारीवादी आन्दोलन के दूसरे दौर की भूमिका आरम्भ होती है जो कि 90 के दशक तक आते-आते नयी चेतना के रूप में विश्व मंच पर स्थापित हो जाती है। कुल मिलाकर सत्ता,स्त्रियों की सामाजिक भूमिका में आए बदलाव पर ध्यान देने को मजबूर हुई। रूस और भारत जैसे देशों में स्त्रियों को घर-बाहर की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। विकासशील देशों में भी बड़ी संख्या में पुरुष बेहतर काम की खोज में शहरों की ओर चले गए। पीछे छूटे परिवार और खेतों की जिम्मेदारी स्त्रियों पर आ पड़ी। इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्त्री की अपनी आत्म छवि भी बदलती गई और उसकी राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी। भारत में इंदिरा गांधी,पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो,अर्जेन्टीना में इजिबेला पेरो,बांग्लादेश में शेख हसीना और खालिदा ज़िया,श्रीलंका में

सिरिमावो भंडारनायके, फिलीपींस में कोटाजोन अक्किनो और इंडोनेशिया में मेघावती सुकर्णपुत्री ने अपनी नेतृत्व क्षमताओं से राजनीतिक दायरे में जबर्दस्त हस्तक्षेप किया।[9]

2.1 भूमंडलीकरण का संक्षिप्त इतिहास:

हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं,[10] भले ही वे हमारी आवश्यकताए हों जैसे -भोजन,कपड़े,फर्नीचर,बिजली का सामान या दवाईयां अथवा आराम और मनोरंजन की वस्तुएं, इनमें से कई भूमंडलीय आकार के नेटवर्क से हम तक पहुंचती हैं। कच्चा माल किसी एक देश का हो सकता है। इस कच्चे माल पर प्रक्रिया करने का ज्ञान किसी दूसरे देश के पास हो सकता है और इस पर वास्तविक प्रकिया किसी अन्य स्थान पर हो सकती है। यह भी हो सकता है कि उत्पादन के लिए पैसा किसी बिल्कुल अलग देश से आया हो। ध्यान दीजिए कि विश्व के विभिन्न भागों में बसे लोग किस प्रकार एक दुसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी परस्पर-निर्भरता केवल वस्तुओं के उत्पादन और वितरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि वे एक-दूसरे से शिक्षा,कला और साहित्य के क्षेत्र में भी प्रभावित होते है। देशों और लोगों के बीच व्यापार,निवेश,यात्रा लोक-संस्कृति और अन्य प्रकार के नियमों से अंतर्क्रिया भूमंडलीकरण की दिशा में एक कदम है। लगभग 200 ई.पू. से 1000 ई.तक पारस्परिक क्रिया और लंबी दूरी तक व्यापार सिल्क रुट के माध्यम से हुआ। सिल्क रूट मध्य और दक्षिण-पश्चिम एशिया में लगभग 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ था और चीन को भारत, पश्चिमी एशिया और भूमंडलीय क्षेत्र से जोड़ता था। सिल्क रुट के साथ वस्तुओं,लोगों और विचारों ने चीन, भारत और यूरोप के बीच हजारों किलोमीटर की यात्रा की। 1000 ई.से 1500 ई. तक एशिया में लंबी-लंबी यात्राओं द्वारा लोगों में वैचारिक आदान-प्रदान होता रहा। इसी दौरान हिन्द महासागर में समुद्रीय व्यवस्था को महत्व मिला। दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य-एशिया के बीच समुद्री मार्ग का विस्तार हुआ। केवल वस्तुओं और लोगों ने ही नहीं, अपितु प्रौद्योगिकी ने भी विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा की। इस अवधि में भारत न केवल शिक्षा एवं अध्यात्म का केन्द्र था, अपितु यहाँ धन-दौलत का भी अपार भंडार था। इसे 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था जिससे आकर्षित होकर विश्व के अन्य भागों से व्यापारी और यात्री यहाँ आए। चीन में मंगोल शासन के दौरान कई चीनी आविष्कार जैसे- कागज,छपाई,धमन भट्टी,रेशम की मशीने,कागज की मुद्रा और ताश

[9]खेतान प्रभा,बाजार के बीच : बाजार के खिलाफ, पृष्ठ संख्या 50,51,52
[10]https//vimi.wordpress.com

यूरोप में पहुंचे। वास्तव में इन्हीं व्यापारिक सम्बंधों ने आधुनिक भूमंडलीकरण का बीजारोपण किया।

अभय कुमार दुबे का मानना है कि विश्व की नई आर्थिक प्रक्रिया जिसे भूमंडलीकरण कहा जा रहा है, को एक ऐसी घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता जिसका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो या जिसका जन्म आकस्मिक रूप से हो गया है। इसकी जड़ें दुनिया की बड़ी शक्तियों, जिन्हें अमीर देश या साम्राज्यवादी शक्तियां भी कहा जाता है,के पारस्परिक युद्धों के बाद हुए उनके विध्वंस में समाहित हैं। इनके विरुद्ध हुए सफल औपनिवेशिक युद्धों से इनके 'दिन दूनी, रात चौगुनी' तरक्की करते हुए आर्थिक तंत्र को इतना आघात पहुंचा कि विश्व में उनका आर्थिक वर्चस्व खतरे में पड़ गया। विश्व की राजनीति में अपने वर्चस्व बनाए रखने और घरेलू मोर्चे पर विकसित होने वाले जन-आन्दोलनों पर अंकुश लगाने के लिए चिंतित इन शक्तिशाली राष्ट्रों में यह खतरा मंडराने लगा कि वे अपने आर्थिक साम्राज्यको पुन:कैसे स्थापित करे। शक्तिशाली देशों की इसी सोच के पश्चात विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नई प्रक्रिया शुरू हुई,जिसे भूमंडलीकरण(ग्लोबलाइजेशन)का नाम दिया जा रहा है।[11]

जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ,तब तक विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के दो धड़ों में विभाजित हो गया था। युद्ध के बावजूद अमेरिका की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुरक्षित थी, फिर भी उसने सोवियत संघ और उसके प्रभाव वाले देशों की तुलना में आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए पश्चिमी यूरोप को अपना निशाना बनाया। वस्तुत:अमेरिका ने यूरोप तथा विश्व के अन्य हिस्सों को अपने और सोवियत संघ के बीच बाँट कर नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचे के इर्द-गिर्द एक सुदृढ़ पश्चिमी पूंजीवादी तंत्र खड़ा कर दिया, ताकि अल्प समय में अमेरिका पूंजी का साम्राज्य खड़ा किया जा सके।

इसी बीच दूसरी नीति के अंतर्गत अमेरिका के नेतृत्त्व में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का गठन किया गया जो अमीर देशों की अर्थव्यवस्था को युद्ध की तबाही से न केवल निकाल लाए बल्कि विश्व में उनका आर्थिक सिक्का भी जमने लगा। इस तरह आर्थिक जगत में एक ऐसी व्यवस्था विकसित होने लगी, जिससे तीसरी दुनिया के देशों के बाजार पर अमीर और शक्तिशाली देशों का कब्जा होने लगा। इन देशों के आर्थिक तंत्र के वैश्विक और सर्वग्राही विस्तार को भूमंडलीकरण का नाम दिया जा रहा है। यह अमीर देशों की दोधारी तलवार है। अमेरिका ने

[11]भूमंडलीकरण और मीडिया, कुमुद शर्मा, प्रकाशक - ग्रंथ अकादमी, नई दिल्ली 110002, संस्करण-प्रथम 2003 पृष्ठ सख्या - 18

भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हथियारों और कूटनीति का इस तरह इस्तेमाल किया है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होना गरीब देशों की मजबूरी बनती जा रही है और वे शक्तिशाली देशों के लिए अपने बाजार खोलते जा रहे है। शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा गरीब देशों को आमंत्रण देकर अपनी व्यापारिक शर्तो को स्वीकार कराने का तात्पर्य दरअसल 'चित भी मेरी और पट भी मेरी' जैसा है। आर्थिक पुनर्निर्माण और व्यापारिक बाधाओं को सशक्त करने के उद्देश्यसे पश्चिमी देशों ने मिलकर चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया जिन्होंने बिना किसी बाधा और विरोध के विश्व में मुक्त व्यापार का मार्ग खोल दिया। ये संस्थाएं हैं - ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम,अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), इन्टरनेशनल मॉनिटरी फंड (विश्व बैंक),वर्ल्ड गैट (जी.ए.टी - जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेडएंडटैरिफ [आयात कर])।[12]

भूमंडलीकरण हमारे समय में सर्वाधिक प्रासंगिक शब्द है। वैयक्तिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन के हर हिस्से पर इसका प्रभाव बेहतर महसूस किया जा रहा है, लेकिन 'वैश्वीकरण' को लेकर अभी तक न तो आम जनता में और न ही बौद्धिक-जगत में कोई स्पष्ट छवि बन पाई है। 'वैश्वीकरण' शब्द की किसी एक परिभाषा पर शायद ही दो व्यक्ति एकमत हों, ऐसे में स्वाभाविक ही है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने में समस्याएं हमारे-सामने होंगी,लेकिन मोटा-मोटी रूप से कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का तात्पर्य एक ऐसे विश्व से है जिसमें राष्ट्रीय सीमाओं और दूरियों से परे एकीकृत आर्थिक,राजनीतिक,सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाएं होंगी। यही कारण है कि कुछ विद्वान 'वैश्वीकरण' शब्द से असहमत हैं और इसकी बजाय 'भूमंडलीकरण', 'अंतर्राष्ट्रीयकरण', 'ब्रह्मांडीयकरण', 'पश्चिमीकरण', 'अमेरिकीकरण', 'बहुराष्ट्रीयकरण' या 'विकेंद्रीकरण' जैसे शब्दों को प्रयुक्त करने का प्रस्ताव करते हैं[13]।

2.2 भूमंडलीकरण और श्रम का स्त्रीकरण:

स्त्रीकरण की पूरी प्रक्रिया को लेकर काफी वाद-विवाद चल रहा है। श्रम के भूमंडलीय महिलाकरण का तर्क गॉय स्टेंडिंग ने दिया। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में काम की अनियमिता और श्रम का महिलाकरण दोनों ही हुए हैं। इसे भारतीय संदर्भ में लागू करते हुए सुधा

[12]भूमंडलीकरण और मीडिया, शर्मा कुमुद पृष्ठ संख्या-19,20

[13]वैश्वीकरण? वैश्वीकरण समर्थन बोधिक छल का खुलासा, सिंह कंवलजीत, अनुवाद-जितेन्द्र गुप्ता पृष्ठ संख्या-8

और एल के देशपांडे का कहना है की महिलाकरण का यह रुझान पूरे भारत और खास्कर मुम्बई में देखने में आया है। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव माना क्योंकि उनके अनुसार इससे महिलाओं के रोजगार के मौके बढ़े हैं। उनका यह भी मानना है कि उदारीकरण से निर्यात बढ़ेगा और निर्यात उद्योग के श्रम प्रधान होने से महिलाओं के श्रम की मांग बढ़ेगी क्योंकि महिला श्रम सस्ता होता है,और महिलाएं ज्यादा आज्ञापालक होती हैं। इसलिए इनके काम से निकाले जाने की सम्भावनाएं भी कम होंगी। महिलाओं के काम के अवसरव्यावसायिक क्षेत्रों में भी बढ़ेंगे और श्रमिक परिवारों की गरीबी कुछ सीमा तक कम होगी। आज के संदर्भ में हमें याद रखना चाहिए कि श्रम बाजार में शोषित होना बुरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा है शोषित न होना। चूंकि उन्हें असंगठित श्रम शक्ति का हिस्सा माना जाता है, इसलिए काम के अनौपचारिक स्वरूप से उन्हें लाभ होने की ज्यादा संभावनाएं हैं।

लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में श्रम का स्त्रीकरण हो रहा है? शहरी और निर्माण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार,श्रम के महिलाकरण के कारण बढ़े हुए जरुर दिखते हैं, लेकिन यह अधिकतर निर्यात प्रक्रिया से संबधित उद्योगों में हुआ है जहां काम की परिस्थितियां काफी कठिन हैं और कम वेतन के साथ ही रोजगार-सुरक्षा नहीं के बराबर है। यहाँ काफी कम वेतन पर अधिकतर गैर-शादीशुदा युवा लड़कियों को काम पररखा जाता है। निर्मला बनर्जी का कहना है कि 1960 और 70 के दशक में भी ऐसे रोजगार उपलब्ध थे,तब भारतीय विदेशी कम्पनियों के ठेकेदार की तरह काम करते थे और तब यह नौकरियां पुरूषों को ही मिलती थीं। इसलिए निश्चिततौर पर नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महिलाओं को पुर्जों और पार्टों को जोड़ने तथा पैकेजिंग के काम दिए जाते हैं जबकि उन्हीं उद्योगों में निगरानी तथा रखरखाव के काम पुरूषों को दिए जाते हैं। तकनीक के प्रवेश से स्थिति और बिगड़ी, वहाँ पुरूषों को बेहतर कामगार माना जाता है। उन उद्योगों में मशीनीकरण के बाद महिलाओं को हटाकर पुरूषों को रखा गया क्योंकि माना गया कि पुरूषों को तकनीकी में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अधिकतर क्षेत्रों में नई तकनीकों के प्रवेश से महिलाओं को काम से हाथ धोना पड़ा है। उदाहरण के लिए इंडियन लीफ टोबैको डिविजन में 25,000 औरतें मशीनीकरण के फलस्वरूप काम से निकाली गईं। पहले तंबाकू की कुटाई हाथ से होती थी, मशीनों से कुटाई शुरू होने पर यह काम पुरूषों को सौंपे गए। यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो पहले गेहूं, धान की बालियों से गेहूं-चावल निकालने का काम कुटाई करके महिला और पुरुष खुद करते थे लेकिन मशीनीकरण के कारण अब वही काम मशीनों से होता है जिससे महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों जैसे निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में

तकनीकों के प्रवेश से महिलाओं के लिए काम के अवसर बढ़े है,लेकिन इसमें केवल शादीशुदा लड़कियों को लिया जाता है। भारत में महिलाएं खेतीबाड़ी के कार्य में और कृषि एवं दस्तकारी की वस्तुओं के निर्माण एवं विपणन के क्षेत्र में पुरूषों की सहायता करती हैं। महिलाओं ने पहले से ज्यादा गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में भी काम करना शुरु कर दिया है लेकिन अब भीशिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश महिलाएं कृषि का काम करती हैं। [14]

2.3 भारतीय स्त्री एवं श्रम : सैद्धांतिक बहसें :

वर्तमान समय में जब दुनिया एक ग्राम के रूप में परिवर्तित हो गई है, हम कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से संसार के किसी भी कोने की जानकारी तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। भूमंडलीकरण का यह दावा है कि इसके जरिए महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बढ़ाया जा रहा है। किन्तु हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण महिला सशक्तिकरण का जो दावा प्रस्तुत करता है, महिलाओं को उसका अपेक्षित फल नहीं मिला है। भूमंडलीकरण ने कुछ बातों में महिलाओं को सशक्त करने का कार्य तो किया है किन्तु बहुत-से क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाएं पहले की अपेक्षा और भी हीन स्थिति में पहुंच गई हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव श्रमिक महिलाओं पर पड़ा है। भूमंडलीकरण से पहले ज्यादातर श्रमकार्य घरों के अंदर किए जाते थे जैसे-कपड़े धुलना, सूत काटना,बर्तन बनाना, जूते बनाना,हस्त-शिल्प व लोहे आदि के काम घरेलू श्रम के अंतर्गत पूरे परिवार द्वारा किए जाते थे जिसमें महिलाओं की भारी संख्या में भागीदारी होती थी किन्तु भूमंडलीकरण के आने के बाद इस तरह के घरेलू काम,उद्योग-धंधे,फैक्ट्रियों के खुलने के कारण बंद हो गए। अब घरों का सारा काम फैक्ट्रियों में होने लगा है जिसके कारण महिलाओं का श्रम छिन गया। फैक्ट्रियों में ज्यादातर संख्या में पुरूषों को ही चुना जाता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं फैक्ट्रियों में काम नहीं करती लेकिन जो महिलाएं घर में इन कामों को अपनी सहूलियत के हिसाब से किया करती थीं, भूमंडलीकरण के बाद अब वही कामफैक्ट्रियों में घंटों के हिसाब से करना होता है। महिलाएं फैक्ट्रियों में जोकाम करती हैं, वो

[14] नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, संपादक : आर्य साधना, मेनन निवेदिता, जिनी लोकनीता प्रथम संस्करण :2001 पृष्ठ संख्या 228,229,230

अधिकतर निम्न स्तर का ही होता है क्योंकि उच्च स्तर पर तो पुरूषों का नियंत्रण है। यहाँ हमें श्रम का लैंगिक विभाजन देखने को मिलता है। श्रम का यह लैंगिक विभाजन असमानता का केन्द्रीय तत्व है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सभी धर्मो को मानने वाले लोग रहते हैं। भारतीय समाज में पितृसतात्मक व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इस व्यवस्था से महिलाओं का प्रत्येक क्षेत्र में शोषण हो रहा है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या राजनैतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र। महिलाओं को हमेशा दोयम दर्जे का माना जाता है। सैद्धांतिक रूप से पुरूषों को उत्पादक माना जाता है जो महिलाओं एवं बच्चों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जबकि महिलाओं को उपभोक्ता माना जाता है जिनकी जगह घर में है और जिनका काम भोजन पकाना और बच्चों की देखभाल करना है। इस प्रकार समाज में महिला व पुरुष के बीच लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है। भूमंडलीकरण के आने से महिलाओं को काम तो मिला लेकिन श्रम का लैंगिक विभाजन आज भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि भूमंडलीकरण के आने के बाद महिलाएं सशक्त नहींहुई। कहने को तो हमारे संविधान मेंसबको जाति,धर्म,लिंग,भाषा,नस्ल आदि के भेदभाव के बिना समान अधिकार प्राप्त है। संविधान में समान काम के लिए 'समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974' बनाया गया है। लेकिन क्या अधिकार दे देने से समाज में समानता आ जाएगी? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज महिलाओं के काम को कोई मूल्य नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनके काम को तो काम ही नहीं माना जाता है। 'लिंग के आधार पर श्रम विभाजन स्त्रियों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के रास्तेमें एक बड़ी बाधा है। इसलिए 'लिंग के आधार पर श्रम विभाजन' को समस्या के रूप में समझना हमारे लिए जरूरी है। आज समाज में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में खुद को आगे ला रही हैं जबकि समाज उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। घर के भीतर सभी कार्यों जैसे–खानाबनाना,बच्चों का पालन-पोषण करना,बड़े-बुजुर्गो की सेवा करना आदि कामों का स्त्रियों एवं पुरूषों के बीच बंटवारा है। दोनों के लिए अलग-अलग कार्य,कर्तव्य और भूमिकाएं निर्धारित हैं। किन्तु अहम बात यह है कि स्त्रियों एवं पुरूषों के बीच काम का यह बंटवारा उनकी पसंदयोग्यता या रुचि के आधार पर नहीं होता है बल्कि लिंग के आधार पर होता है। भूमंडलीकरण से महिलाओं को काम के क्षेत्र तो मिले हैं लेकिन साथ ही अब उन्हें दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। अब वे घर के काम के साथ-साथ बाहर का काम भी करती हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन को हम सीधा-सीधा विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। इसका संबंध आर्थिक विकास से है। महिलाएं दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा हैं जिनके बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संयुक्त

राष्ट्र संघ ने महिला तथा विकास पर 1975 में मैक्सिको में एक सम्मेलन आयोजित किया और 1975-85 के दशक को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक' घोषित किया। महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओंतथा कार्यवाहियों की शुरुआत हुई जिन्हें लगभग सभी सदस्य सरकारों का समर्थन मिला। विश्व के अनेक हिस्सों में इस विषय पर चर्चा के लिए सैकड़ोंसभाएं और सम्मेलन किए गए कि किस प्रकार औरतों को विकास का हिस्सा बनाया जाए।

मारिया मिस के अनुसार, 'लिंग आधारित श्रम विभाजन को एक पारिवारिक समस्या के रूप में देखने के बजाय सम्पूर्ण रूप से समाज की एक ढाँचागत समस्या के रूप में देखना चाहिए। मर्दों तथा औरतों के बीच श्रम विभाजन का ऊंच-नीच होना तथा उससे जुड़ी गतिविधियां,उत्पादन सम्बंधों (यानि एक खास समय और एक खास समाज के वर्ग सम्बंध तथा व्यापक रूप से राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन) का एक हिस्सा हैं।[15] औरत के उत्पादन तथा पुनरुत्पादन को कोई खास आर्थिक अहमियत नहीं दी जाती। 1995 की संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की 'मानव विकास रिपोर्ट'के मुताबिक औरतों के अदृश्य तथा अवचेतन श्रम योगदान की वार्षिक कीमत 110 खरब या 11 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है।[16] मर्द घर के भीतर औरत द्वारा किए जाने वाली मेहनत और घर के बाहर कमाई के लिए की जाने वाली मजदूरी दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। घर के भीतर औरतें परिवार के बच्चों, पतियों तथा अन्य सदस्यों के लिए जीवन भर मेहनत करती रहती हैं। सिल्विया वैल्बी इसे 'उत्पादन की पितृसतात्मक प्रणाली' का नाम देती हैं। इसके तहत पति तथा परिवार के अन्य सदस्य औरत की मेहनत का फायदा उठाते हैं। वह कहती हैं कि घरेलू औरतें उत्पादन करने वाला वर्ग है और पति फायदा उठाने वाला वर्ग है। औरत केचौबीसो घंटे चलने वाले उबाऊ और कमरतोड़ मेहनत वाले काम को काम ही नहीं समझा जाता और उसे पति पर निर्भर व्यक्ति के रूप में देखा जाता है।

domestic labor work :-मार्क्सवादी नारीवाद सबसे ज्यादा आलोचना करता है वेश्यावृति की। ये किसी औरत का खुद का चुनाव नहीं है बल्कि समाज का है। भागलपुर प्राचीन व प्रसिद्ध शहर है जहां महिलाएं वेश्यावृति का काम करती हैं। उत्पादन वाले कार्यों में वो गतिविधियां आती हैं, जो उपभोग और व्यापार के लिए वस्तुएं और सेवाएँ प्रदान करती हैं। यह सारा कार्य फैक्ट्रियों,दफ्तरों और खेतों में किया जाता है और देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में इसे गिना जाता है। ये सभी गतिविधियां आर्थिक कहलाती हैं और यहाँ सीधे तौर पर आदमी

[15] भला ये जेंडर क्या है? कमला भसीन, अनुवाद:वीणा शिवपुरी,सातवा पुनर्मुद्रण,दिसम्बर 2014,नई दिल्ली 110017

[16] पितृसता क्या है? कमला भसीन,अनुवाद: वीणा शिवपुरी,आठवा संस्करण:जून 2014,नई दिल्ली 110017

और औरतों के बीच लैंगिक विभाजन दिखता है। औरतों को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आदमी वे काम करते हैं जिनमें ज्यादा दक्षता की आवश्यकता है और जो अच्छी कमाई वाले होते हैं जबकि औरतों को वे काम करने होते हैं जो एक तरह से उनके घरेलू कामों का हीविस्तार होता है। खेतों में किया जाने वाला काम इसी वर्ग में आता है। उन्हें सीधे रूप में कोई आर्थिक लाभ नहीं होता और शायद यही वजह है कि औरतों के काम को कम महत्व और बेमूल्य समझा जाता है। आदमी कमाने वाला माना जाता है और घर का मालिक भी होता है। भूमंडलीकरण से महिलाओं को काम तो मिला है लेकिन इससे उनकी भूमिका में परिवर्तन नहीं आया है। अब महिलाओं को घरेलू कामों,बच्चों का पालन-पोषण और घर की देख-रेख के अलावा बाहर के काम भी करने होते हैं। जैसे-अगर एक महिला घर से बाहर जॉब करती है तो उसके घर में कोई दूसरी महिला मेड बनकर उसकी अनुपस्थिति में घर को संभालती है और तीसरी उसके बच्चे की देखभाल करती है। भूमंडलीकरण से महिला को काम काक्षेत्र तो मिला है पर दूसरी तरफ उसकी भूमिका दोहरी हो गई है और इस दोहरी भूमिका में दोहरा श्रम एवं दोहरा शोषण दोनों शामिल है।

UNDP- मानव विकास रिपोर्ट (1995) में बताया गया है कि महिलाएं साल में 11 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कार्य करती हैं। डॉ.मनमोहन हिंदी के प्रोफेसर हैं और उनका कहना है कि जिस दिन महिला श्रम का हिसाब होगा, उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी।घर एक ऐसा स्पेस है जिसकी तुलना नहीं की जाती क्योंकि जो महिलाएं घर पर काम करती हैं,उन्हें उसका मूल्य नहीं मिलता है। मार्क्सवादी-नारीवादी इस पर सवाल करते हैं किइस पर महिलाओं एवंपुरुषोंदोनों को प्रश्न करने की जरूरत है कि आखिर ये सब क्यों किया जाता है। बाहर काम करने पर पैसा मिलता है, लेकिन घर के अंदर किए जाने वाले काम का कोई मूल्य नहीं दिया जाता है।

मार्क्सवादी-नारीवादी मानते हैं कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला घरेलू श्रम, श्रम-बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके इस काम का आर्थिक मूल्य निर्धारित नहीं है। घर के बाहर भी स्त्रियों को मिलने वाला काम घरेलू श्रम का ही विस्तार होता है।

Margaret Benston (1969) – मार्गरेट बेंस्टन कहती हैं कि स्त्रियाँ घर में जो काम करती है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि उनके द्वारा किए जाने वाले काम अनुत्पादक काम हैं। जब तक घरेलू कार्य का सामाजीकरण नहीं होगा, तब तक श्रम-व्यापार में स्त्रियों का पदार्पण उनकी मुक्ति की कामना को पीछे धकेलने वाला ही होगा।

Dala Costa डेला कोस्टामार्क्सवादी विचारकहैं जो घरेलू कामों के आर्थिक मूल्य को निर्धारित करने की बात करती हैं क्योंकि घरेलू श्रम-बाजार के श्रम से पैदा होने वाला अधिशेष (सरप्लस) कुल अधिशेष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

एलिसन जैग़र कहती हैं कि शासन श्रम का औजार ही नहीं श्रम की उपज भी है।

एन ओकले का विचार है कि श्रम के लैंगिक विभाजन पर आधारित लिंग भूमिकाओं का निर्धारण जैविक रूप की बजाय सांस्कृतिक रूप से होता है।उनका तर्क है कि महिलाओं के लिए श्रम विभाजन महिलाओं की जैविक विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए।

आपने एक कहावत तो सुनी होगी किहर कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। क्योंकि एक महिला ही घर के अंदर पति, भाई को बाहर काम पर भेजने के लिए,खाना बनाने से लेकर उनके कपड़े धोने तक के सारे काम करती है। प्रत्येक महिला कहीं-न-कहीं अदृश्य रूप से अपनी भूमिका निभाती है, तभी पुरुष घर से बाहर जाकर काम करता है। दूसरी तरफ भूमंडलीकरण से जहां महिलाओं को रोजगार मिला, वहीं महिलाओं की स्थिति पहले से ज्यादा बिगड़ गई क्योंकि अब वह घर के कामों के साथ ही बाहर के काम भी करती है। महिला घर के अंदरप्राकृतिक रूप से बच्चे पैदा करती हैलेकिन अब सरोगेसी के रूप में वह सार्वजनिक दायरे में लोगों की कम्पनी के लिए भी वही काम कर रही है। पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महिला फैक्ट्री में मजदूर/स्वायतता बनाए रखने के लिए जैसे:-पितृसता के मूल्यों को utilizen करने में महिला अहम भूमिका निभाती है।

सिमोन द बोउआ - स्त्री पैदा नहीं होती,बनाई जाती है।

इटली और ग्रीस में जूते के ऊपरी हिस्से की सिलाई औरतें अपने घरों में करती हैं।

नीदरलैंड,इग्लैंड और अमेरिका में गाड़ियों के छोटे-छोटे कलपुर्जे घरों पर बनते हैं।

थाईलैंड में घरेलू श्रमिक,अमेरिका को निर्यात करने के लिए अपने घरों में प्लास्टिक की चीजें बनातेहैं।

भारत में वस्त्र उद्योग का सीधा सम्बंध घरेलू उद्योग से है। घर में बैठकर औरतें पेटीकोट,ब्लाउज,बच्चों के कपड़े,बीड़ी,धूपबत्ती,पापड़ आदि बनाती हैं। ये किस रेट पर बनते हैं? फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग है,वहाँ मुस्लिममहिलाएं चूड़ी बनाने के काम में काँच को

पिघलाने,रंगों को अलग-अलग करनेजैसे सारे काम करती है ।[17]विकासशील देशों में महिला मजदूरों की स्थिति पर कोई भी टिप्पणी तब तक अधूरी रहेगी ,जब तक कि कृषि में महिलाओं की स्थिति पर विचार न किया जाए। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक हिस्सों में दो-तिहाई से ज्यादा श्रम-शक्ति कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों में लगी है। इन देशों में भू-स्वामित्व का ढांचा भी काफी असमानताओं वाला है। अधिकांश परिवार या तो भूमिहीन है या उनके पास भूमि का बहुत छोटा सा टुकड़ा है । इस तबके में उपार्जन गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी,पुरूषों की भागीदारी के करीब-करीब बराबर ही होती है। वे या तो दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करती हैं या घरेलू मजदूरी करती हैं। पुरूषों व महिलाओं की गतिविधियों में आमतौर पर श्रम का स्पष्ट विभाजन रहता है। हालांकि क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी मौजूद रहती हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में धान की खेती के दौरान खेत में की जाने वाली निराई-गुड़ाई,खेत जोतना, धान रोपना,फसल कटाई आदि पुरूषों की जिम्मेदारी होती है। औरतें बीजों को संभालना,फटकना, उनके छिलके निकलना आदि घर के नजदीक या घर में रहकर किए जाने वाले काम करती हैं। जबकि भारत में धान रोपने का कार्य महिलाएं करती हैं, किन्तु ऐसी क्षेत्रीय भिन्नताओं के अतिरिक्त मोटे-मोटे तौर पर स्त्री-पुरुष का श्रम-विभाजन लगभग एक-सा ही रहता है। जैसा कि जया मेहता, 'भूमंडलीकरण में महिलाओं का श्रम'नामक किताब में महिलाओं के श्रम के बारे में बता रही हैं, वैसी ही स्थिति हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले की भी है ।मेरा शोध कुरुक्षेत्र जिले पर ही है ।यह जिला अपने आप में ऐतिहासिक है और यहाँ भी ज्यादातर महिला-पुरुष कृषि में ही कार्यरत हैं ।यहां पर भी महिलाएं बीजों को सम्भालनेफटकने, उनके छिलके निकालनेका काम करती हैं। जहां तकफसल लगाने की बात है जैसेचावल की खेती तो महिलाएं ज्यादा संख्या में चावल की पौध को लगाती हैं ।यहाँ पर महिलाएं घर का सारा काम कर, सुबह-सुबह अपने बच्चों को स्कूल और पति को ड्यूटी पर भेज कर खुद दूसरों के खेतों में जाकर काम करती हैं। इस प्रकार के काम ज्यादातर निम्न वर्ग की महिलाएं करती हैं। मूंग की दाल जब पक कर तैयार हो जाती है तो उसे तोड़ने के लिए दिहाड़ी पर गाँव से महिलाओं को बुलाया जाता है, क्योंकि उनका श्रम सस्ता होता है। वहीं दूसरी ओर पुरुष खेतों को जोतने,फसल को पानी देने और दवाईयों के छिड़काव के लिए निम्न वर्ग के लोगों को दिहाड़ी पर लाते हैं। ऐसा नहीं है किवहाँ के लोग खेतों में काम नहीं करते। जो लोग काम करते है,उनके खुद के खेत होते हैं और वे उच्च वर्ग के लोग होते हैं। इससे निम्न वर्ग का शोषण हो रहा है। जब गेहूं, चावल की फसल

[17] भूमंडलीकरण में महिलाओं का श्रम, जय मेहता,अनुवाद: विनीत तिवारी,तीसरा संस्करण-जनवरी 2004,प्रकाशक:संदर्भ इंदौर(म.प्र.)-4520001 पृष्ठ संख्या 32,33

पक कर तैयार हो जाती है, तब पुरुष स्वयं फसल को मण्डी में ले जाकर बेचता है। महिलाओं को दिहाड़ी या जो रेट गाँव के लोगों द्वारा बता दिया जाता है, वही मिलता है। इसमें पुरुष भी शामिल हैं। फसल को लगाने और उसको बेचने के बाद जो पूँजी मिलती है, वो पुरूषों के नियन्त्रण में रहती है। उच्च वर्ग की महिलाएं तो खेतों में जाकर भी नहीं देखती हैं। कुछ महिलाओं को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके खेतकहाँ पर हैं।[18]

अधिकांश जगहों पर दिहाड़ी के लिए पुरूषों के बजाय महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि उनकी मजदूरी कम है और इसलिए भी क्योंकि मशीनीकरण ने महिलाओं की तुलना में पुरूषोंके रोजगार ज्यादा खत्म किए हैं। इसकेबाद भी दिहाड़ी पर काम करने वाले पुरुष वमहिलाएं अभी भी बहुत हैं क्योंकि कृषि में बड़ी पूंजी के प्रवेश ने इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार नम्यता (Elasticity) को भयंकर तरह से घटा दिया है। मैक्सिको में 1 करोड़ लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। उन्हें अबाबीलों की ब्रिगेड कहा जाता है। तीसरी दुनिया के देशों में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, उनका परिणाम यह निकला कि महिलाओं पर काम का बोझ तो काफी बढ़ गया,लेकिन न तो उनकी आमदनी में उचित अनुपात में वृद्धि हुई और न ही संसाधनों पर उनको कोई नियन्त्रण मिला। किन्तु यहाँ यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं की यह विशेष गरीबी;समूचे कृषि मजदूरों पर आए हुए संकट से अलग नहीं है,बल्कि इसे समस्त कामगार तबके पर आयी तकलीफों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। महिलाओं की इस समस्या का हल केवल उन्हें कृषि अधिकार या सम्पत्ति अधिकार देकर ही नहीं पाया जा सकता,बल्कि इन समस्याओं का समुचित हल, पूंजी व श्रम के बीच के बेमेल को सुलझाकर ही पाया जा सकता है।

'कृषि क्षेत्र में लगी महिलाओं की समस्याएं' लेख में 'मनोज कुमार मिश्र' द्वारा लिखा गया है कि आज के भौतिक युग से हमारे जीवन-मूल्य इस कदर प्रभावित हैं कि कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य से सबसे ज्यादा हमारा समाज प्रभावित हुआ है। 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में 27.06 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं और 48.83 प्रतिशत कृषक मजदूर हैं। इस प्रकार भारत में कृषि क्षेत्र महिलाओं के रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र है और आज की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भारत की प्राय: सभी महिलाओं को किसीन किसी रूप में किसान माना जा सकता है। ग्रामीण भारत एक ऐसी प्रक्रिया के दौर से गुजर रहा है

[18] भूमंडलीकरण में महिलाओं का श्रम, जय मेहता,अनुवाद: विनीत तिवारी,तीसरा संस्करण-जनवरी 2004,प्रकाशक:संदर्भ इंदौर(म.प्र.)-4520001 पृष्ठ संख्या 34

जिसे 'कृषि क्षेत्र के महिलाकरण' की संज्ञा दी जा रही है। 1977 और 1991 की अवधि के दौरान कृषक मजदूरों की तुलना में महिला कृषक मजदूरों का अनुपात 57%से बढ़कर 60 % हो गया है। 1961 की जनगणना में काम की काफी विस्तृत परिभाषा दी गयी थी और जनगणना में महिलाओं के काम की काफी भागीदारी दिखी लेकिन वहां भी केवल वैतनिक काम को ही काम माना गया था। फिर 1971 की जनगणना में एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी कम दिखी। 1981 और 1991 की जनगणना में इन कामों की पहचान बनी, अत: इसमें फिर महिलाओं की अपेक्षाकृत ज्यादा भागीदारी दिखती है।1980 में पहला सम्मेलन बुलाया गया असंगठित क्षेत्रों के श्रमिको को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया। 1991 में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी तो देखी गई, लेकिन नीतियों के स्तर पर कोई परिवर्तन आता नहीं दिखाई देता कि घरों में किए जाने वाले काम को आप काम मानेंगे या नहीं ?

1961,1971 के काल में सामाजिक परिवर्तन आता दिखता है,जब कई तरह के सामाजिक आन्दोलन एवं श्रमिक आन्दोलन हो रहे थे। स्त्री रोजगार व जनन क्षमता पर 1985 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन {International Labor Organization(ILO)}द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि खनन एवं परिवहन को छोड़कर लगभग हर पेशे व उद्योग में महिलाएं मौजूद थीं।[19]भूमंडलीकरण व्यापने के बावजूद दुनिया के कई देशों में मजदूर दिवस सरकारी छुट्टी का दिन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्य भारत में ऐसा नहीं है। और तो और इस भारत देश में ऐसी कोई परम्परा नहीं बन पाई है जिससे मजदूरों के संदेशों को दूसरी नहीं तो कम-से-कम उनकी अपनी जमातों तक पहुंचाया जा सके। तथ्यों के अनुसार, '19 वीं शताब्दी के नवे दशक तक मजदूर अत्यंत अल्प व अनिश्चित मजदूरी पर 16 घंटे तक काम करने को अभिशप्त थे। 1810 के आसपास ब्रिटेन में उनके सोशलिस्ट संगठन 'न्युलेनार्क' ने रॉबर्ट ओवेन की अगुवाई में अधिकतम 10 घंटे काम की मांग उठाई और उसके 6-7 सालों बाद 8 घंटे काम पर जोर देना शुरू किया। उनके संघर्ष के बावजूद 1847 तक मजदूरों की राह सिर्फ इतनी आसान हो पाई थी कि इग्लैंड के महिला एवं बाल मजदूरों को अधिकतम 10 घंटे काम की स्वीकृति मिल गयी थी। आस्ट्रेलिया में 21 अप्रैल 1856 को स्टोनमेंशन और मेलबर्न के आसपास के बिल्डिंग कर्मचारियों ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर हड़ताल और मेलबर्न विति से पार्लियामेंट हॉउस तक प्रदर्शन किया तो 1866 में जेनेवा कन्वेंशन में इंटरनेशनल व क्रिग मेंस एसोसिएशन ने भी इस हेतु अपनी आवाज बुलंद की। निर्णायक घड़ी 1 मई 1886 को तब आयी,जब अमेरिका के शिकागो में हड़ताली मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया और वहाँ की

[19] http//wwprabhathabar.com

पुलिस, नेशनल गार्ड और घुड़सवार दस्ते ऐसे बर्बर दमन पर उतर आएकि शिकागो की धरती रक्त से लाल हो गई। तभी से उस संघर्ष की याद में हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है।